(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां पर एक भी सरकारी/गैर-सरकारी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है; और

(घ) ऐसे जिलों में उद्योग स्थापित करने और ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है।

उद्योग मंत्रालय लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, नहीं। देश में कई जिलों/क्षेत्रों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है जिसमें कुछ केन्द्र सरकार द्वारा और अन्य राज्य सरकारें द्वारा घोषित किए गए हैं और इन क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन/रियायतें दी जाती हैं जिनमें परिवहन राजसहायता, आधारभूत विकास के लिए केन्द्रीय सहायता और विकास केन्द्र योजना महत्वपूर्ण हैं। हाल में की गयी दूसरी अखिल भारतीय गणना के अनुसार 5,82,368 चालू एककों में से मात्र लघु उद्योग विकास संगठन के अधीन 3,62,174 एकक पिछड़े क्षेत्रों में स्थित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न आदिवासी उपयोजना (टी०एस०पी०) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं कार्य करती रही है जिसमें आधारभूत सुविधाओं के विकास और उद्योगों की स्थापना पर भी बल दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूसरी अखिल भारतीय गणना के अनुसार लघु उद्योग विकास संगठन के अधीन सभी जिलों में एकक कार्य कर रहे हैं।

(घ) जहां औद्योगिक विकास उचित स्तर पर नहीं है वहां इसे और गति देने के लिए निरंतर आधार पर विशेष प्रोत्साहन रियायतें दी जा रही हैं। इसके अलावा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन लक्ष्य समूह के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में आय उत्प्रेरक परिसम्पतियां प्राप्त करने के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्रों में राजसहायता और ऋण दिये जा रहे हैं।

New Growth Centre Schemes

426. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the status of implementation of New Growth Centre Scheme allotted to Karnataka, for promotion of industrially backward areas, located at Dharwar, Hassan and Raichur, and

(b) whether Government would set a time frame to make these projects fully functional?

THE MINISTER OF STATE IS THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Under the Growth Centre Scheme announced in June, 1988, the State of Karnataka has been allotted 3 growth centres to be located one each in the districts of Dharwar, Hassan and Raichur. These projects have been approved and Central assistance of Rs. 2 crores for each Centre has been released.

(b) The scheme is to be implemented during the VIII Five Year Plan period.

Small scale and big industries in Bihar

427. SHRI GAYA SINGH: Will the PRIME MINISTER to pleased to state:

(a) what is the total number of small and big industries of the Central Government in Bihar;

(b) what is the total earning of the Central Government and the State Government on this account; and

(c) what is the number of side industries at present and what are the details of Government's scheme to make them viable?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Growth of paper industry

428. SHRI P. UPENDRA: Will the PRIME MINISTER to pleased to state:

(a) whether it is a fact that the growth of paper industry in the country is highly disappointing;

(b) whether it is also a fact that the industry has suggested a suitable policy package in consonance with the new industrial policy; and

(c) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) There has been a steady growth in the Paper and Paper Board Industry. The Paper and Paper Board Industry is meeting the entire domestic demand and the imports are few, mainly restricted to some speciality papers such as art paper, cheque paper, photo-base paper, high strength craft paper, filter paper, cable and condenser paper, etc.

(b) and (c) There is constant interaction between the Government and the Industry and suitable policy measures are taken by Government whenever necessary.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाना

429. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिये किसी उपक्रम के संबंध में कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में बनायी गई कार्यनीति का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों और संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्यम विशेष की आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाती है। उठाए गए सामान्य कदम इस प्रकार हैं:

(I) सरकारी क्षेत्र और अधिक उपक्रमों को समझौता ज्ञापन के विचार क्षेत्र में लाया गया है जिसका उद्देश्य कार्य-निष्पादन में सुधार करना है।

(II) 38 रुग्ण उपक्रमों को उनके पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी योजना बनाने हेतु औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंप दिया गया।

(III) कार्य-निषपादन में सुधार हेतु उठाए गए अन्य कदमों का विवरण 5.3.1992 को सभा पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1990-91 के खण्ड-I के अध्याय 9 के पैरा 15.1 (पृष्ठ सं॰ 165) में दिया गया है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, हटिया की वित्तीय स्थिति

430. **श्री गया सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, हटिया की वित्तीय स्थिति क्या है और अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 तक की अवधि में इस कंपनी को कितना लाभ या हानि हुई है;

(ख) सरकार इस उद्योग का विकास करने और इसे